

शिव चंदर मोरे व अन्य

बनाम

उपराज्यपाल व अन्य

(2014 की सिविल अपील संख्या 3352)

7 मार्च, 2014

[टी. एस. ठाकुर और सी. नागप्पन, जे. जे.]

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (भूमि कार्यकाल) विनियम, 1926:

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह राजस्व और भूमि सुधार विनियमन,
1966: नियम 144

1926 विनियम के तहत भूखंड का अनुदान-कोई नया अनुदान या नवीनीकरण नहीं-1926 विनियम का निरसन-चाहे 1966 का विनियम हो। विनियम अनुदान प्राप्तकर्ता को कोई भी अधिकार प्रदान करते हैं जिसका अनुदान जब विनियमन 151 के तहत गिने गए आधारों में से एक प्रशासन को उनकी बेदखली के लिए उपलब्ध हो जाता है-आयोजित: यदि किसी अवधि समाप्त अनुदान के अनुदानकर्ता ने दायित्व वहन किया था प्रदत्त संपत्ति के कब्जे को समर्पण करने के लिए, ऐसा दायित्व के निरसन के बावजूद प्रवर्तनीय रहेगा जिन विनियमों के तहत ऐसा दायित्व उत्पन्न हुआ-विनियम

144 1966 के विनियमों में निर्धारित किया गया है कि पुराने के तहत एक अनुदान प्राप्तकर्ता नियम एक ही दायित्व के तहत बने रहेंगे / दायित्व या समान अधिकारों का आनंद लें जो इसके तहत अनुमत हैं 1966 विनियम-इस प्रकार, विनियम का सार जहाँ तक किसी अनुदान प्राप्तकर्ता का अधिकार कब्जा में बने रहने का है वर्ष 1966 के बाद के विनियम-इनमें से किसी एक में मामलों में, अनुदान प्राप्तकर्ता 60 वर्षों से अधिक समय तक कब्जे में नहीं रह सकता है। यह तर्क कि एक पुराना अनुदानकर्ता स्थायी रूप से कब्जे में रह सकता है जब तक कि इसका कोई उल्लंघन नहीं होता है विनियम 151, मान्य नहीं है-अपीलार्थी, तत्काल इस मामले में, निस्संदेह 1966 के विनियमों के तहत संरक्षण था क्योंकि 1994 तक उनके पक्ष में नवीनीकृत अनुदान में था 1966 में अस्तित्व में था लेकिन इस तरह का संरक्षण 1994 में 60 साल की अवधि की समाप्ति के साथ समाप्त हो जाएगा।

रेस जुडीकाटा:

रचनात्मक रेस जुडीकाटा लिखित कार्यवाहियों के लिए प्रयोज्यता-चर्चा की गई।

कंस्ट्रक्टिव रेस जुडीकाटा-भूमि के भूखंड का अनुदान 1926 नियम-नए अनुदान के लिए अपीलार्थी के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया उपराज्यपाल द्वारा-लिखित याचिका-उच्च न्यायालय ने लिया यह विचार कि

अधिभोगियों को भूमि से बेदखल करने की आवश्यकता नहीं है केवल तब तक जब तक किसी भी जनता के लिए इसकी आवश्यकता नहीं थी उद्देश्य-उच्च न्यायालय के समक्ष, अपीलार्थी ने कोई मुद्दा नहीं उठाया यह तर्क कि चाहे नया अनुदान उनके पक्ष में दिया गया हो या नहीं और चाहे दूसरा अनुदान दिया गया हो या नहीं 1966 के विनियमन के तहत एक निहित अधिकार प्राप्त किया था उक्त अधिनियम के विनियम 151 के तहत गणना की गई आकस्मिकताओं में से एक तक भूमि पर कब्जा करना जारी रखें। उन्हें जारी रखने से वंचित करने वाले नियम उत्पन्न हुए भूमि पर कब्जा-उक्त विवाद के लिए उपलब्ध था उनके द्वारा उस स्तर पर क्योंकि रहने वालों ने नहीं किया मुकदमे के पिछले दौर में इस तरह के विवाद का आग्रह करते हैं तत्काल कार्यवाही में ऐसा करने से वर्जित हैं रचनात्मक न्यायपालिका के सिद्धांत-अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (भूमि कार्यकाल) विनियम, 1926.

प्रथम अपीलार्थी के दादा और पिता शेष अपीलार्थियों में से एक को अंडमान और निकोबार के संदर्भ में 30 वर्ष की अवधि के लिए भूमि प्रदान की गई थी। द्वीप (भूमि कार्यकाल) विनियम, 1926। 30 वर्षों की उक्त अवधि 1964 में समाप्त हो गई। राजस्व प्रशासन ने भूमि पर फिर से कब्जा करने की मांग की। अनुदान प्राप्तकर्ता ने उसी को चुनौती दी और यह माना गया कि वर्ष 1974 तक भूमि राजस्व प्राप्त करने वाले विभाग को नवीनीकरण से

इनकार नहीं करना चाहिए और अनुदान प्राप्तकर्ता थे। खाली करने के लिए कहा। मामला उच्च न्यायालय के समक्ष आया जिसमें अनुदान प्राप्तकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारियों को अनुमति दी गई थी। नए अनुदान के लिए एक प्रतिनिधित्व। ऐसा कोई अभ्यावेदन दायर नहीं किया गया और राजस्व विभाग ने फिर से जारी किया खाली करने के लिए नोटिस। अनुदान प्राप्तकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारियों ने याचिका दायर की। लेफ्टिनेंट के समक्ष दिनांक 8 और 15 मई, 2000 राज्यपाल ने उनके पक्ष में एक नए अनुदान के लिए जो खारिज कर दिए गए। इनके खिलाफ रिट याचिकाओं को फिर से अनुमति दी गई उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा। हालांकि, डिवीजन बेंच ने एकल न्यायाधीश के आदेश को इस निर्देश के साथ संशोधित किया कि यदि विचाराधीन भूमि की आवश्यकता है सार्वजनिक उद्देश्य के लिए प्रशासन, यह प्राप्त करने के लिए कानून के उचित प्रावधानों का सहारा लेने का हकदार होगा एक ही। उपराज्यपाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की न्यायालय जहाँ यह अभिनिर्धारित किया गया था कि मूल अनुदान प्राप्तकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा दायर अभ्यावेदन उनके पक्ष में एक नए अनुदान के लिए थे और आगे अभिनिर्धारित किया कि दूसरा नवीकरण को उचित रूप से अस्वीकार्य माना गया था उपराज्यपाल। इसलिए, उपायुक्त ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए निर्देश दिया कि भूमि का अधिकार

सौंपने के लिए अपीलार्थी। द रिट उपायुक्त के निर्देश को चुनौती देने के लिए याचिका दायर की गई थी। उच्च न्यायालय ने रिट खारिज कर दी इस आधार पर याचिका कि अपीलार्थी नहीं थे नवीकरण से इनकार करने से संबंधित कोई भी प्रश्न उठाने का अधिकार या उनके पक्ष में एक नया अनुदान।

तत्काल अपील में, दो अलग-अलग प्रश्न जो विचार के लिए उठे थे वे थे: चाहे वह अपीलार्थियों को इस आधार पर भूमि से बेदखल करने का विरोध करने से रोक दिया गया था कि उन्होंने अधिग्रहण कर लिया है नवीकरण के बिना भी कब्जे में बने रहने का अधिकार और अंडमान और [2014] 4 एस. सी. आर. के तहत उनके पक्ष में एक नया अनुदान। निकोबार द्वीप समूह भूमि राजस्व और भूमि सुधार विनियम, 1966; और (2) क्या 1966 विनियम वास्तव में अनुदान प्राप्तकर्ताओं को कोई भी अधिकार प्रदान किया जाता है जिनके रहने के लिए अनुदान समय के साथ समाप्त हो गया है जब तक विनियमन 151 के तहत गिने गए आधारों में से एक उपलब्ध नहीं हो जाता है तब तक अधिकार उनके निष्कासन के लिए प्रशासन।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा अभिनिर्धारित किया की:

प्रश्न संख्या 1

1. 8 और 15 मई, 2000 को उपराज्यपाल को संबोधित अभ्यावेदनों द्वारा, अपीलार्थी उनके पक्ष में एक नए अनुदान की मांग की। उनकी प्रार्थना

थी। 28 फरवरी, 2001 के अपने आदेश द्वारा पूर्व द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने ये अभ्यावेदन दायर किए थे जाहिरा तौर पर क्योंकि उच्च न्यायालय ने यह विचार रखा था कि अनुदान का दूसरा नवीनीकरण अनुमत नहीं था 1926 के विनियमों के तहत। दाखिल करना अभ्यावेदन स्पष्ट रूप से स्वीकार करने के बराबर था उस स्थिति की शुद्धता। आदेश से व्यथित उपराज्यपाल द्वारा पारित, रिट-याचिकाकर्ता उन्होंने फिर से उच्च न्यायालय का रुख किया। यह उनके लिए यह तर्क देने के लिए खुला था कि चाहे कोई नया अनुदान हो उनके पक्ष में किया गया या नहीं और इस बात की परवाह किए बिना कि 1926 के तहत दूसरा नवीनीकरण अनुमत था या नहीं। विनियमों के तहत, उन्होंने एक निहित अधिकार प्राप्त किया था 1966 भूमि पर कब्जा तब तक जारी रखने के लिए विनियमन जब तक कि निम्नलिखित आकस्मिकताओं में से एक न हो उक्त विनियमों के विनियम 151 ने रिट-याचिकाकर्ताओं/कब्जाधारियों को भूमि पर कब्जा जारी रखने से वंचित कर दिया। इस तरह की याचिका को उठाया जा सकता था और वास्तव में उठाया जाना चाहिए था यदि अपीलकर्ता निर्णय के लिए उस मुद्दे को आंदोलन करने का इरादा रखते थे। हालाँकि, उक्त मामले में उच्च न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई तर्क नहीं दिया गया था। याचिका। इसके विपरीत, उच्च न्यायालय ने दृष्टिकोण लिया कि कब्जाधारियों को केवल तब तक भूमि से बेदखल करने की

आवश्यकता नहीं है जब तक कि किसी भी जनता के लिए इसकी आवश्यकता न हो उद्देश्य। उच्च न्यायालय ने 1966 के विनियमों का उल्लेख किया यह सुझाव देने के लिए कि एक नया अनुदान इसके तहत भी अनुमत था उसके उक्त विनियम के उपबंध। यह है, इसलिए, यह स्पष्ट है कि न केवल रिट-याचिकाकर्ता बल्कि उच्च न्यायालय भी 1926 के निरसन के प्रति सचेत था 1966 के विनियमों द्वारा विनियम और नए अनुदान की अनुमति देने वाले बाद के विनियमों के प्रावधान। इसलिए, इसे रहने वालों को रोकने की आवश्यकता नहीं थी (अपीलार्थी) उच्च न्यायालय के समक्ष आग्रह करने से क्योंकि वे अब ऐसा प्रतीत होता है कि 1966 के विनियम वे चाहे जो भी हों, व्यवसाय में बने रहने के हकदार हैं क्या उनके पक्ष में अनुदान का नवीनीकरण किया गया था और चाहे कुछ भी हो या न हो, एक नया अनुदान था भूमि के संबंध में। अब विवाद की मांग की गई। विनियम 151 निवासियों के लिए उपलब्ध था जिसे उस स्तर पर उनके द्वारा उठाया जा सकता था और वास्तव में उठाया जाना चाहिए था। क्योंकि रहने वालों ने किसी से आग्रह नहीं किया था ऐसा मुद्दा या पिछले में इस तरह का कोई विवाद उठाएँ सैद्धांतिक रूप से रचनात्मक न्यायपालिका रिट कार्यवाही पर भी लागू होती है। रेस जुडिकाटा का सिद्धांत एक है न्यायशास्त्र के सबसे बुनियादी और सुव्यवस्थित नियम। यह सिद्धांत सभी सभ्य कानूनी प्रणालियों में पाया जाता

है। संसार में समाज। यह दो गुना तर्क पर आधारित है, अर्थात्, (1) सक्षम न्यायालय द्वारा निर्णय लेने की अंतिमता होनी चाहिए और (2) किसी भी व्यक्ति को दो बार परेशान नहीं किया जाना चाहिए। एक ही कारण से। ये दो सिद्धांत आकर्षित करते हैं अंतर-पक्षीय निर्णयों के लिए भी न्यायिक निर्णय का सिद्धांत जो कानून के प्रश्न पर गलत हो सकते हैं। रचनात्मक रेस जुडिकाटा जो भी इसका एक हिस्सा हैं एक ही सिद्धांत को रिट कार्यवाही पर लागू माना गया है। [पैरा 18 और 19] [433-एफ-एच; 434-ए-एच; 435 ए-डी, एच]

उपराज्यपाल और अन्य। वी. शिव चंदर मोरे और अन्य। 2008 (4) एससीसी 690: 2008 (6) एस. सी. आर. 106; एकीकृत कोलफील्ड्स लिमिटेड और ए. एन. आर. वी. जनपद सभा छिंदवाड़ा और अन्य। ए. आई. आर. 1964 एससी 1013: 1963 पूरक। एस. सी. आर. 172-पर निर्भर।

1.2. यह अब अपीलार्थियों के लिए बहस करने के लिए खुला नहीं है कि रचनात्मक न्यायपालिका के सिद्धांत नहीं होंगे उन्हें सवाल उठाने से रोकें जो हो सकता है और वास्तव में उनके द्वारा पूर्व में उठाया जाना चाहिए था मुकदमेबाजी का दौर। उच्च न्यायालय, मामले के उस दृष्टिकोण में, यह अभिनिर्धारित करने में पूरी तरह से उचित था कि याचिका की मांग की गई थी इस न्यायालय के आदेशों द्वारा उन्हें दी गई स्वतंत्रता के कथित प्रयोग में

अपीलार्थियों द्वारा उठाया जाना था कानूनी रूप से खुला नहीं है और आग्रह करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। [पैरा 22] [437-बी-सी]

प्रश्न सं। 2

2.1. 1966 के विनियमों का विनियम 141 किरायेदारों के वर्गों को वर्गीकृत करता है जबकि विनियम 142 और विनियम 143 अधिभोग किरायेदारों और गैर-अधिभोग के साथ सौदा करें क्रमशः किरायेदार। यह सामान्य आधार है कि अपीलार्थी अधिभोग के विवरण का उत्तर नहीं देते हैं। के अर्थ के भीतर किरायेदार या गैर-अधिभोग किरायेदार विनियम 142 और विनियम 143। उनका मामला विनियमन 144 के तहत अधिक उचित रूप से आता है जो दोनों वर्गों में से किसी से भी संबंधित व्यक्तियों से संबंधित है। खंड (ए) और (बी) इसके तहत। ऐसा इसलिए है क्योंकि अपीलार्थियों को 1926 के विनियमों के विनियम 4 (1) (ए) के तहत अनुदान प्राप्तकर्ता माना गया था जो इससे अलग है। उक्त अधिनियम के विनियम 4 (1) (बी) के तहत आने वाले लाइसेंसधारी 1966 के विनियमों के विनियम या विनियम 145। हालाँकि, सवाल यह है कि क्या शिव चंद्र मोर वी के तहत कोई अनुदान प्राप्तकर्ता है। 1926 विनियमों को व्यवसाय में बने रहने का कोई भी अधिकार है 60 वर्ष की अवधि से परे, जो 1966 के विनियम 146 के तहत अनुमेय अवधि है। यह विवाद में नहीं है कि 1926 के विनियमों के तहत ऐसा

कोई अधिकार नहीं पाया जा सकता है। की समाप्ति जैसा कि हाथ में मामला है, अनुदान की अवधि अनुदान प्राप्तकर्ताओं को कब्जा सौंपने के लिए बाध्य करेगी प्रशासन। 1926 के विनियमन के तहत किया गया वह दायित्व या दायित्व अच्छा बना हुआ है, वर्ष 1966 के विनियमों द्वारा 1926 के विनियमों के निरसन के बावजूद। [पैरा 27] [442-बी-एफ]

2.2. यदि किसी अवधि समाप्त अनुदान के अनुदानकर्ता ने प्रदान की गई संपत्ति के कब्जे को सौंपने का दायित्व वहन किया था, ऐसे दायित्व उन विनियमों के निरसन के बावजूद प्रवर्तनीय रहेंगे जिनके तहत ऐसा दायित्व है। उठ खड़ा हुआ। यह तर्क कि 1966 के विनियमों के विनियम 144 (1) (ए) के कारण दायित्व समाप्त हो जाता है, कानूनी रूप से अनुचित है। सबसे पहले, क्योंकि विवाद उड़ता है विनियमन 211 के सामने जो जारी है 1926 के विनियमों के तहत किया गया दायित्व। जब तक किए गए दायित्व को मान्यता दी जाती है और निरसन विनियमन द्वारा जारी रखा जाता है, तब तक इसे कानून में लागू किया जा सकता है। दूसरा, क्योंकि विनियमन की व्याख्या 144 (1) (क) स्वयं ऐसी स्थिति को स्वीकार नहीं करता है जहाँ निरंतरता में। वह सब जो विनियमन 144 निर्धारित करता है वह यह है कि पुराने नियमों के तहत अनुदान प्राप्तकर्ता एक ही दायित्व/दायित्व के तहत बना रहेगा या उसी का आनंद लेगा। अधिकार जो 1966 के विनियमों के तहत

अनुमत हैं। द. हालाँकि जारी रखने का अधिकार इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या व्यवसाय में व्यक्ति के पक्ष में एक वैध अनुदान है, यहां तक कि 1966 के विनियम लागू होने की तारीख से। यदि उत्तर सकारात्मक है, तो इस तरह के अनुदान को 1966 के विनियमों के तहत अनुदान माना जा सकता है, चाहे वह कुछ भी हो। वास्तव में 1926 के विनियमों के तहत एक अनुदान। [पैरा 28] [443 एफ-एच; 444-ए-सी]

2.3. अनुदान की अप्राप्त अवधि की सीमा तक, जैसे -उस तारीख को, 1966 के विनियम लागू हुए, अनुदानकर्ता अपने अधिकार का आनंद लेता रहेगा और 1966 के विनियमों के तहत दायित्व के अधीन होगा। समाप्ति के बाद अनुदान की अवधि, हालांकि, अनुदान प्राप्तकर्ता कब्जा सौंपने के लिए उत्तरदायी होगा जैसा कि अनुदान प्राप्तकर्ता करने के लिए उत्तरदायी है। के तहत किए गए अनुदान के संबंध में विनियमन 146 के तहत 1966 नियम। विनियमन का सार इस प्रकार है जहाँ तक किसी अनुदान प्राप्तकर्ता का अधिकार है कि वह अपने कब्जे में बना रहे संबंधित, 1926 के विनियमों के तहत समान है और वर्ष 1966 के बाद के विनियम। दोनों में से जिन मामलों के लिए अनुदान प्राप्तकर्ता कब्जे में नहीं रह सकता है 60 वर्ष से अधिक। यह तर्क कि एक पुराना अनुदानकर्ता जब तक विनियमन 151 का कोई उल्लंघन नहीं होता है, तब तक स्थायी रूप से कब्जे में रह सकता है, इसलिए इसे

अस्वीकार किया जा सकता है। अपीलार्थी, तत्काल मामले में, इसमें कोई 59 संदेह नहीं है 1966 के विनियमों के तहत संरक्षण हो सकता है क्योंकि उनके पक्ष में अनुदान को 1994 तक नवीनीकृत किया गया था जो 1966 में अस्तित्व में था, लेकिन इस तरह के 1994 में 60 साल की अवधि की समाप्ति के साथ संरक्षण समाप्त हो जाएगा। [अनुच्छेद 29 और 30] [444-डी-एच]

रतन कौर बनाम। भारत संघ और ओआरएस। (1997) 10 एससीसी 61: 1997 (1) पूरक। एस. सी. आर. 48; डेविलल मोदी बनाम। एस. टी. ओ. एयर 1965 एससी 1150: 1965 एससीआर 686; प्रत्यक्ष भर्ती वर्ग- / / इंजीनियरिंग अधिकारी संघ। वी. महाराष्ट्र राज्य (1992) 2 एससीसी 715; डायरेक्ट रिक्रूट क्लास-॥ इंजीनियरिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन। वी. महाराष्ट्र राज्य (1992) 2 एस. सी. सी. 715-संदर्भित।

निर्णय जिनका उल्लेख किया गया

1997(1) पूरक। एससीआर 48 उल्लेख किया गया है	पैरा 11
2008 (6) एससीआर 106 इस पर भरोसा किया	पैरा 18
1963 पूरक। एससीआर 172 इस पर भरोसा किया	पैरा 18
1965 एससीआर 686 उल्लेख किया गया है	पैरा 19

(1992) 2 एस. सी. सी. 715 उल्लेख किया गया है पैरा 20

सिविल अपीलिय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 3352/2014

2011 के एम. ए. टी. सं. 4 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के दिनांक 31.01.2011 के निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थियों के लिए प्रमोद कोहली, निपू पातिरी, राजीव तलवार।

उत्तरदाता के लिए जी. दारा, शादमान अली, शैलेंद्र सैनी, रश्मि मल्होत्रा,
डी. एस. माहरा, आर. बालासुब्रमण्यन, के. वी. जगदीशवरन

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

टी. एस. ठाकुर, जे.

1. अनुमति दी गयी।

2. यह अपील कलकत्ता उच्च न्यायालय, पोर्ट ब्लेयर में सर्किट बेंच द्वारा पारित 31 जनवरी, 2011 के एक फैसले और आदेश से उत्पन्न हुई है, जिसके तहत अपीलकर्ताओं द्वारा दायर 2011 के MAT नंबर 004 को खारिज कर दिया गया है और 20 दिसंबर के आदेश को खारिज कर दिया गया है। 2010 को उस न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा 2008 की रिट याचिका संख्या 174 को खारिज करते हुए पारित किया गया।

3. तथ्यात्मक मैट्रिक्स जिसमें विवाद उत्पन्न होता है, उस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के साथ-साथ उपराज्यपाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह द्वारा पारित दिनांक 28 फरवरी, 2001 के आदेश में काफी विस्तार से निर्धारित किया गया है। विवरण के बिना हम इसे संक्षेप में निम्नानुसार दोहरा सकते हैं:

4. विटोबा, प्रथम अपीलकर्ता के दादा और शेष अपीलकर्ताओं के पिता को विनियम 4(1) के अनुसार दक्षिण अंडमान जिले में फेरागंज तहसील की सीमा के भीतर 43 एकड़, 12 कनाल और 10 मरला भूमि का एक भूखंड आवंटित किया गया था। (बी) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (भूमि स्वामित्व) विनियमन, 1926। पार्टियों के बीच लंबी चली कार्यवाही के कुछ चरण में, निर्धारण के लिए उठने वाले मुद्दों में से एक यह था कि क्या प्रश्न में अनुदान विनियमन के संदर्भ में दिया गया था ऊपर उल्लिखित विनियम के 4(1)(ए) या 4(1)(बी)। अंडमान और निकोबार प्रशासन (संक्षेप में 'प्रशासन') का विचार था कि यद्यपि अनुदान विनियम 4(1)(बी) के तहत फॉर्म बी में दिया गया था, लेकिन वास्तव में यह विनियम 4(के तहत अनुदान था) 1)(ए) तत्संबंधी। विवाद का वह हिस्सा अब हमारे सामने विचार के लिए नहीं बचा है। हमारे समक्ष प्रस्तुत प्रस्तुतियाँ सामान्य आधार पर आगे बढ़ीं कि अनुदान

वास्तव में एक था, जो कि प्रश्नगत विनियम के विनियम 4(1)(ए) के तहत दिया गया था।

5. विटोबा के पक्ष में दिया गया अनुदान विनियम 4(1)(ए) के अनुसार 30 वर्षों की अवधि के लिए वैध था, लेकिन 30 वर्षों की एक और अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता था। ऐसा प्रतीत होता है कि वर्ष 1964 में 30 वर्षों की प्रारंभिक अवधि समाप्त होने के साथ, प्रशासन ने विचाराधीन भूमि पर पुनः कब्जा करने का निर्णय ले लिया है क्योंकि धारक के पक्ष में अनुदान के नवीनीकरण का कोई आदेश नहीं दिया गया था। उस दिशा में उपायुक्त ने 26 अप्रैल, 1974 को एक आदेश पारित किया, जिससे राम चंद्र विटोबा, पुत्र और श्रीमती व्यथित हुए। मृत अनुदान प्राप्तकर्ता की विधवा डैन देई ने उपायुक्त द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए सचिव, अंडमान और निकोबार प्रशासन के समक्ष अपील दायर की। राजस्व सचिव ने यह कहते हुए अपील का निपटारा कर दिया कि राजस्व विभाग को वर्ष 1974 तक कब्जेदारों से भू-राजस्व प्राप्त हुआ है, यह कहने में बहुत देर हो चुकी है कि अनुदान का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।

6. उपर्युक्त अपील में राजस्व सचिव द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, राजस्व अधिकारियों ने भूमि संपत्ति के लिए देय राजस्व को फिर से तय किया और मूल अनुदान प्राप्तकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारियों को 1994 तक कब्जा

जारी रखने की अनुमति दी, जिसके बाद विस्तारित अवधि अनुदान की राशि भी समाप्त हो गई, हालांकि कब्जाधारियों के पक्ष में अनुदान का कोई औपचारिक विस्तार/नवीकरण नहीं किया गया था। कुल 60 वर्ष की अवधि की समाप्ति के साथ, श्रीमती। राम चंद्र विटोबा की पत्नी संगीता बाई को प्रशासन के पक्ष में भूमि संपत्ति जारी करने के लिए बुलाया गया था क्योंकि यह विकासात्मक उद्देश्यों के लिए आवश्यक था। उक्त निर्देश से व्यथित होकर श्रीमती. राम चंद्र मोरे की पत्नी संगीता बाई और वर्तमान रिट-याचिकाकर्ता की मां ने पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता उच्च न्यायालय, सर्किट बेंच के समक्ष 1994 की रिट याचिका संख्या 72 दायर की। उस न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने अन्य बातों के साथ-साथ यह कहते हुए 2 दिसंबर, 1994 को उक्त रिट याचिका का निपटारा किया:

"इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता का भूमि पर कोई अधिकार नहीं है क्योंकि 1934 में उसके पूर्ववर्तियों के पक्ष में दी गई लीज विस्तारित अवधि सहित 1994 में भूमि राजस्व और भूमि सुधार विनियमन के अनुसार समाप्त हो गई थी।" 1966. ऐसे में याचिकाकर्ता के लिए उपलब्ध एकमात्र उपाय अपने नारियल बागान के संबंध में नए अनुदान के लिए

संबंधित प्राधिकारी को एक अभ्यावेदन देना है, जो याचिकाकर्ता के पूर्ववर्ती, मूल लाइसेंसधारी को दिया गया था। तदनुसार याचिकाकर्ता को स्वतंत्रता दी जाती है तिथि से चार सप्ताह के भीतर ऐसा अभ्यावेदन देना होगा और यदि ऐसा अभ्यावेदन दिया जाता है, तो संबंधित प्राधिकारी उसके ऐसे अभ्यावेदन पर यह विचार करते हुए विचार करेंगे कि याचिकाकर्ता का पूर्ववर्ती लाइसेंस के रूप में प्रश्नाधीन भूमि के कब्जे का आनंद ले रहा था, निश्चित रूप से तिथि से 4 महीने के भीतर ऐसा अभ्यावेदन करने का। अभ्यावेदन के निस्तारण के तीन सप्ताह बाद तक आज की स्थिति यथास्थिति जारी रहेगी।"

7. उपरोक्त आदेश अंतिम हो गया क्योंकि रिट-याचिकाकर्ता द्वारा अपील में इसे चुनौती नहीं दी गई थी। अनुदान का दूसरा नवीनीकरण विनियमों के तहत अस्वीकार्य माना गया था। उच्च न्यायालय ने फिर भी अनुदान प्राप्तकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारियों को नारियल बागान के संबंध में अपने पक्ष में नए अनुदान के लिए प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी। ऐसा कोई अभ्यावेदन दायर नहीं किए जाने पर, कानूनी उत्तराधिकारियों अर्थात् श्रीमती को 20 जुलाई, 1998 को एक नया नोटिस जारी किया गया था। संगीता बाई मोरे और सात अन्य को उपायुक्त ने जमीन का भौतिक कब्जा सरकार को सौंपने

के लिए कहा। उक्त नोटिस प्राप्त होने पर, मूल अनुदान प्राप्तकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारियों में से एक, श्री शिव चंद्र मोरे ने उच्च न्यायालय के समक्ष 1998 की रिट याचिका संख्या 54 दायर की, जिसे उच्च न्यायालय ने 16 नवंबर, 1998 को एक बार फिर यह कहते हुए निपटा दिया। अनुदान के दूसरे नवीनीकरण के लिए कोई प्रावधान नहीं था लेकिन अनुदान प्राप्तकर्ता अपने पक्ष में नए अनुदान के लिए आवेदन कर सकते थे। रिट याचिका का निपटारा याचिकाकर्ताओं को उनके कब्जे वाली भूमि के संबंध में नए अनुदान के लिए उपराज्यपाल के समक्ष एक लिखित अभ्यावेदन दाखिल करने के निर्देश के साथ किया गया, जिस पर प्रशासन को सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का निर्देश दिया गया था।

8. उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश के बावजूद रिट-याचिकाकर्ताओं ने कोई प्रतिनिधित्व प्रस्तुत नहीं किया और भूमि पर संयुक्त कब्जा जारी रखा। तदनुसार, उपायुक्त ने अनुदान प्राप्तकर्ता के उत्तराधिकारी को भूमि का भौतिक कब्जा तहसीलदार, फेरागंज को सौंपने के लिए एक नोटिस जारी किया। उक्त नोटिस की प्राप्ति के बाद ही रिट-याचिकाकर्ताओं ने अपने पक्ष में नए अनुदान के लिए उपराज्यपाल के समक्ष दो याचिकाएं दायर कीं, एक दिनांक 8 तारीख और दूसरी 15 मई, 2000। उक्त अभ्यावेदन पर उपराज्यपाल द्वारा विचार किया गया और 28 फरवरी, 2001 के अपने आदेश द्वारा अस्वीकार कर दिया

गया। उपराज्यपाल ने अनुदान प्राप्तकर्ताओं के पक्ष में नए अनुदान से इनकार करने के दो मुख्य कारण बताए। सबसे पहले, यह कहा गया था कि यद्यपि 1966 के विनियमों में एक प्रावधान था जिसने 1926 के विनियमों को निरस्त कर नया अनुदान देने का प्रावधान किया था, प्रशासन ने पुराने अनुदानों के नवीनीकरण के बाद केवल एक अवधि के लिए अनुमति के अनुसार किसी को भी कोई नया अनुदान नहीं दिया था। नियमों के तहत. इसके विपरीत, ऐसे अनुदानों के तहत सभी भूमियों को उस अवधि की समाप्ति के बाद प्रशासन द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया, जिसके लिए उनका नवीनीकरण किया गया था। उपराज्यपाल ने माना कि मौजूदा मामले में, अनुदान प्राप्तकर्ताओं ने 1.1.1934 से 67 वर्षों से अधिक समय तक विचाराधीन भूमि पर कब्जा कर लिया था।

9. उपराज्यपाल ने रिट-याचिकाकर्ताओं के पक्ष में नया अनुदान देने से इनकार करते समय जो दूसरा कारण दिया, वह यह था कि अनुदान प्राप्तकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों के पास शोर प्वाइंट और बम्बूफ्लैट में संपत्ति थी और उक्त भूमि में से कुछ उनके पास थी। इसका उपयोग उन घरों और इमारतों के निर्माण के लिए किया गया था जिन्हें व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किराए पर दिया गया था। इसलिए, रिट-याचिकाकर्ताओं को नए अनुदान से इनकार करने से याचिकाकर्ता भूमिहीन नहीं हो जाएंगे। उपराज्यपाल ने कहा:

"चूंकि रिट याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों के नाम पर शोर प्वाइंट/बैंबूफ्लैट पर 6.35 हेक्टेयर भूमि है और चूंकि अनुदान की बहाली पर उन्हें बेघर नहीं किया जाएगा, इसलिए वे अनुदान को नवीनीकृत कराने के हकदार नहीं हैं। पक्ष। इसलिए, याचिकाकर्ता की याचिका खारिज की जाती है और अभ्यावेदन का निपटारा किया जाता है।"

10. उपराज्यपाल द्वारा पारित आदेश से व्यथित होकर, मूल अनुदान प्राप्तकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष 2001 की रिट याचिका संख्या 91 दायर की, जिसे उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने अपने आदेश दिनांक 18 सितंबर, 2001 द्वारा अनुमति दी थी। उच्च न्यायालय ने माना कि चूंकि याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों ने काफी धनराशि खर्च करके भूमि का विकास किया था, इसलिए उन्हें तब तक भूमि से बेदखल करने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि ऐसी भूमि की वास्तव में किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवश्यकता न हो। यदि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है, तो याचिकाकर्ता या कोई अन्य व्यक्ति उस भूमि पर दावा बरकरार रखने का हकदार नहीं होगा, क्योंकि उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अन्य सभी प्रयोजनों पर प्राथमिकता दी होगी। लेकिन जब तक प्रश्नगत भूमि की वास्तव में किसी

सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता न हो, तब तक याचिकाकर्ता या उसके परिवार के सदस्यों का कब्जा नहीं तोड़ा जाना चाहिए और न ही भूमि का कब्जा किसी अन्य व्यक्ति को सौंपा जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने कहा:

"तदनुसार, उपराज्यपाल को निर्देश दिया जाता है कि वह याचिकाकर्ता को तब तक जमीन अपने पास रखने की अनुमति दें जब तक कि किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए वास्तव में इसकी आवश्यकता न हो और इस उद्देश्य के लिए, यह आवश्यक है, उपराज्यपाल नया लाइसेंस दे सकते हैं। हालाँकि, यदि कोई ऐसा नया लाइसेंस है उपराज्यपाल द्वारा इसे "किसी भी परिस्थिति में लाइसेंस के नवीनीकरण के रूप में नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि कोई दूसरा नवीनीकरण स्वीकार्य नहीं है।" याचिकाकर्ता को उस स्थिति में उक्त भूमि का शांतिपूर्ण और खाली कब्जा सौंपना होगा, जिसकी वास्तव में आवश्यकता है। प्रतिवादी प्राधिकारियों को किसी विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजन के लिए और विशेष रूप से तब जब सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की मांग करने वाले प्रतिवादी प्राधिकारियों द्वारा पूर्व सूचना दी जाएगी। उपराज्यपाल याचिकाकर्ता को नया लाइसेंस

देने से पहले याचिकाकर्ता से एक वचन पत्र प्रस्तुत करने के लिए भी कह सकते हैं। इसलिए 28 फरवरी, 2001 को उपराज्यपाल द्वारा पारित आदेश को ऊपर बताए गए तरीके से संशोधित किया गया है।"

11. उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के उपरोक्त आदेश के खिलाफ दायर 2001 की MAT संख्या 28 को 6 फरवरी, 2002 के आदेश द्वारा निपटाया गया था, जिसके द्वारा डिवीजन बेंच ने एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को इस निर्देश के साथ संशोधित किया था कि यदि प्रशासन को सार्वजनिक प्रयोजन के लिए विचाराधीन भूमि की आवश्यकता है, तो वह इसे प्राप्त करने के लिए कानून के उचित प्रावधानों का सहारा लेने का हकदार होगा। डिवीजन बेंच ने माना कि रतन कौर बनाम भारत संघ और अन्य में इस न्यायालय का निर्णय । (1997) 10 एससीसी 61 का मामले में कोई आवेदन नहीं था क्योंकि इसे एक अलग तथ्य स्थिति में दिया गया था।

12. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से व्यथित होकर उपराज्यपाल ने 2004 के सीए संख्या 5091 में इस न्यायालय में अपील की। इस न्यायालय ने माना कि मूल अनुदान प्राप्तकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा दायर अभ्यावेदन उनके पक्ष में एक नए अनुदान के लिए थे। इस न्यायालय ने आगे कहा कि दूसरे नवीनीकरण को उपराज्यपाल द्वारा उनके द्वारा पारित

आदेश में और रतन कौर के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय द्वारा अनुचित माना गया था। इस न्यायालय ने तदनुसार उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि उपराज्यपाल द्वारा पारित आदेश कानूनी और उचित था। इस न्यायालय ने कहा:

"इसलिए, उपराज्यपाल का आदेश कानूनी और उचित था और उच्च न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। यदि प्रतिवादी के पास नए अनुदान और/या नवीनीकरण की मांग के अलावा कोई उपाय है, जैसा कि दावा किया गया है, तो वह छूट नहीं जाएगा। उपराज्यपाल और उच्च न्यायालय के समक्ष अभ्यावेदन पर विचार के लिए। हम उस संबंध में कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं। लागत के संबंध में किसी भी आदेश के बिना अपील को उपरोक्त सीमा तक अनुमति दी जाती है।"

13. उपायुक्त द्वारा पारित 23 जून, 2008 के आदेश से मुकदमेबाजी का एक नया दौर शुरू हुआ, जिसके तहत उपायुक्त ने इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए याचिकाकर्ताओं को तारीख से 15 दिनों के भीतर विषय भूमि का कब्जा सौंपने का निर्देश दिया। उक्त आदेश की प्राप्ति नहीं होने पर, तहसीलदार, फेररगंज को सरकार को भूमि बहाल करने के लिए कानून के अनुसार उचित कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया गया था। उपायुक्त द्वारा

जारी निर्देश को चुनौती देने के लिए दायर रिट याचिका संख्या 174/2008 ने न केवल उपायुक्त द्वारा जारी आदेश की आलोचना की, बल्कि उत्तरदाताओं को विवादित भूमि पर उनके कब्जे में हस्तक्षेप न करने का निर्देश देने के लिए एक परमादेश के लिए भी प्रार्थना की। उस याचिका को अंततः उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता इस न्यायालय के फैसले और पारित आदेशों के आलोक में अपने पक्ष में नवीनीकरण या नए अनुदान से इनकार करने से संबंधित कोई भी प्रश्न उठाने के हकदार नहीं थे। कार्यवाही के प्रारंभिक चरण में, उच्च न्यायालय ने यह विचार किया कि एक बार जब याचिकाकर्ताओं को नया अनुदान देने से इनकार करने वाले उपराज्यपाल द्वारा पारित आदेश को इस न्यायालय द्वारा कानूनी और वैध माना गया था, तो उक्त आदेश को किसी भी चुनौती के लिए कोई जगह नहीं थी और न ही यह खुला था। याचिकाकर्ताओं को यह तर्क देना होगा कि वे अपने पक्ष में दूसरे नवीनीकरण या नए अनुदान के हकदार थे। एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ दायर की गई लेटर्स पेटेंट अपील भी विफल रही, मूल अनुदान प्राप्तकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारियों ने उक्त आदेशों का विरोध करने के लिए वर्तमान अपील दायर की है।

14. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री कोहली ने तर्क दिया कि मुकदमे के पिछले दौर में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश

ने अपीलकर्ताओं के लिए भूमि के विवादित हिस्से से किसी अन्य आधार पर अपनी बेदखली का विरोध करने के लिए पर्याप्त जगह छोड़ दी है। दो आधारों पर पहले आग्रह किया गया था, अर्थात् पहले के अनुदान का नवीनीकरण या उनके पक्ष में एक नया अनुदान। यह तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता, उनके द्वारा दायर नई रिट याचिका में, न तो अनुदान के दूसरे नवीनीकरण के अधिकार का दावा कर रहे थे और न ही वे अपने पक्ष में नए अनुदान का दावा कर रहे थे क्योंकि मुकदमे के पहले दौर में ये दोनों पहलू उनके खिलाफ थे। फिर भी अपीलकर्ता यह तर्क देने के हकदार थे कि उन्होंने 1966 के विनियमों के अनुसार तब तक कब्जा जारी रखने का अधिकार प्राप्त कर लिया था जब तक कि उनका मामला उक्त विनियमों के विनियम 151 में उल्लिखित एक या अन्य आकस्मिकताओं के अंतर्गत नहीं आता। विद्वान वकील के अनुसार, यह एक आधार था जो 9 अप्रैल, 2008 के अपने आदेश में इस न्यायालय द्वारा उनके लिए आरक्षित स्वतंत्रता के कारण अपीलकर्ता के लिए उपलब्ध था। हालांकि उच्च न्यायालय ने यह विचार किया था कि ऐसा कोई विवाद नहीं है रचनात्मक निर्णय के सिद्धांत पर अपीलकर्ता द्वारा आग्रह किए जाने पर उच्च न्यायालय गलती में पड़ गया। विद्वान वकील के अनुसार, इस सवाल का कोई निर्धारण नहीं था कि क्या अपीलकर्ताओं ने नवीनीकरण या अपने पक्ष में नए पट्टे/लाइसेंस का दावा करने के अधिकार से स्वतंत्र 1966

के विनियमन के तहत भूमि पर कब्जे में रहने का कोई अधिकार हासिल किया था। इसके अलावा, विद्वान वकील के अनुसार, यह सवाल कि क्या नवीनीकरण या नए पट्टे के बिना भी कब्जा जारी रखने का अधिकार नहीं था और न ही उठाया जा सकता था, मुकदमे के पिछले दौर में उठाया गया था ताकि पुनर्न्याय के सिद्धांत को आकर्षित किया जा सके या अंतर्निहित सिद्धांत समान हैं।

15. उत्तरदाताओं की ओर से श्री बालासुब्रमण्यम द्वारा यह तर्क दिया गया कि मुकदमेबाजी का वर्तमान दौर कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। यह प्रस्तुत किया गया था कि इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना है कि उपराज्यपाल द्वारा पारित आदेश कानूनी और वैध था, इस सवाल पर किसी और बहस के लिए कोई जगह नहीं थी कि क्या अपीलकर्ता नवीनीकरण या नए अनुदान के हकदार थे। उन्होंने आग्रह किया कि अपीलकर्ताओं को 1966 के विनियमन के तहत भी किसी भी लाभ का दावा करने से रोक दिया गया था क्योंकि ऐसे किसी भी लाभ का दावा उनके द्वारा मुकदमे के पिछले दौर में किया जा सकता था और वास्तव में किया जाना चाहिए था जिसमें अपीलकर्ता नवीनीकरण या वैकल्पिक रूप से नए सिरे से दावा कर रहे थे। उनके पक्ष में अनुदान. इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा उपायुक्त द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप को अस्वीकार करना उचित था, विद्वान वकील ने तर्क दिया।

16. हमारे विचार के लिए दो अलग-अलग प्रश्न उठते हैं। ये हैं:

1) क्या अपीलकर्ताओं को इस आधार पर भूमि से बेदखली का विरोध करने से रोका गया है कि उन्होंने 1966 के विनियमन के तहत नवीनीकरण और अपने पक्ष में नए अनुदान के बिना भी कब्जा जारी रखने का अधिकार हासिल कर लिया है; और (2) क्या 1966 के विनियम वास्तव में उन अनुदानग्राहियों को अधिकार प्रदान करते हैं जिनका अनुदान समय के साथ समाप्त हो गया है, जब तक कि विनियम 151 के तहत गिनाए गए आधारों में से एक उनके निष्कासन के लिए प्रशासन के पास उपलब्ध नहीं हो जाता, तब तक वे कब्जा में बने रहेंगे।

17. हम प्रश्नों से सिलसिलेवार निपटने का प्रस्ताव करते हैं। पुनः प्रश्न संख्या 1

18. उपराज्यपाल को संबोधित 8 और 15 मई, 2000 के अभ्यावेदन में रिट-याचिकाकर्ताओं के पक्ष में नए अनुदान की मांग की गई। उनकी प्रार्थना को उनके 28 फरवरी, 2001 के आदेश द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से ये अभ्यावेदन दायर किए थे क्योंकि उच्च न्यायालय ने यह विचार किया था कि 1926 के विनियमों के तहत अनुदान का दूसरा नवीनीकरण स्वीकार्य नहीं था। अभ्यावेदन दाखिल करना स्पष्ट रूप से उस स्थिति की सत्यता को स्वीकार करने जैसा है। उपराज्यपाल द्वारा

पारित आदेश से व्यथित होकर, रिट-याचिकाकर्ताओं ने 2001 के WP संख्या 91 में फिर से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। यह उनके लिए यह तर्क देने के लिए खुला था कि चाहे उनके पक्ष में एक नया अनुदान दिया गया हो या नहीं और इस पर ध्यान दिए बिना कि क्या या 1926 के विनियमों के तहत दूसरे नवीनीकरण की अनुमति नहीं थी, उन्होंने 1966 के विनियमों के तहत भूमि पर कब्जा जारी रखने का एक निहित अधिकार प्राप्त कर लिया था, जब तक कि उक्त विनियमों के विनियम 151 के तहत गिनाई गई आकस्मिकताओं में से एक रिट-याचिकाकर्ताओं को अधिकार से वंचित न कर दे। /कब्जाधारियों को भूमि पर कब्जा जारी रखने से रोका जाए। यदि अपीलकर्ताओं का इरादा निर्णय के लिए उस मुद्दे को उठाने का था तो ऐसी याचिका वास्तव में उठाई जानी चाहिए थी। हालाँकि, उक्त याचिका में उच्च न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई तर्क नहीं दिया गया था। इसके विपरीत, उच्च न्यायालय ने यह विचार किया कि कब्जाधारियों को भूमि से बेदखल करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए इसकी आवश्यकता न हो। उच्च न्यायालय ने यह सुझाव देने के लिए 1966 के विनियमों का उल्लेख किया कि उक्त विनियम के प्रावधानों के तहत भी एक नया अनुदान स्वीकार्य था। इसलिए, यह स्पष्ट है कि न केवल रिट-याचिकाकर्ता बल्कि उच्च न्यायालय भी 1966 के विनियमों द्वारा 1926 के

विनियमों को निरस्त करने और नए अनुदान की अनुमति देने वाले बाद के विनियमों के प्रावधानों के प्रति सचेत था। ऐसा होने पर, कब्जाधारियों (यहां अपीलकर्ताओं) को उच्च न्यायालय के समक्ष आग्रह करने से रोकने की आवश्यकता नहीं है जैसा कि वे अब कर रहे हैं, कि 1966 के विनियम उन्हें कब्जे में बने रहने का अधिकार देते हैं, भले ही अनुदान का नवीनीकरण हुआ हो या नहीं। उनके पक्ष में और चाहे या न हो, भूमि के संबंध में एक नया अनुदान था। अब इस विवाद में आग्रह किया गया है कि कब्जेधारी बिना नवीनीकरण के या अपने पक्ष में नए अनुदान के बिना भी विवादित भूमि पर हमेशा के लिए कब्जा जारी रख सकते हैं, केवल इस शर्त पर कि उन्होंने विनियमन 151 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया है। कब्जेदारों को उस स्तर पर उठाया जा सकता था और वास्तव में उठाया जाना चाहिए था। हालाँकि, कब्जेदारों ने इस तरह के किसी मुद्दे पर आग्रह नहीं किया था या मुकदमे के पिछले दौर में इस तरह का कोई विवाद नहीं उठाया था, जो 2004 के सिविल अपील संख्या 5091 में उपराज्यपाल और अन्य के इस न्यायालय के आदेश के साथ समाप्त हुआ था। बनाम शिव चंद्र मोरे और अन्य 2008 (4) एससीसी 690 में रिपोर्ट की गई, उन्हें रचनात्मक निर्णय के सिद्धांतों पर वर्तमान कार्यवाही में ऐसा करने से रोका गया है। सैद्धांतिक रूप से यह रचनात्मक न्यायिक न्याय रिट कार्यवाही पर भी लागू होता है, जो इस

न्यायालय के कई निर्णयों द्वारा काफी अच्छी तरह से तय किया गया है। हम संक्षेप में उन कुछ निर्णयों का उल्लेख कर सकते हैं जो सिद्धांत को विस्तृत करते हैं और रिट न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में उनके आवेदन का विस्तार करते हैं। लेकिन ऐसा करने से पहले, हमें यह कहना होगा कि घिसा-पिटा क्या है, यानी कि पुनर्न्याय का सिद्धांत न्यायशास्त्र के सबसे मौलिक और सुस्थापित नियमों में से एक है। यह सिद्धांत दुनिया के सभ्य समाज की सभी कानूनी प्रणालियों में पाया जाता है। यह दोहरे तर्क पर आधारित है, अर्थात्,

(1) कि सक्षम न्यायालय द्वारा निर्णय को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए और

(2) किसी भी व्यक्ति को एक ही कारण के लिए दो बार परेशान नहीं किया जाना चाहिए। ये दो सिद्धांत अंतर-पक्षीय निर्णयों के लिए भी पुनर्न्याय के सिद्धांत को आकर्षित करते हैं जो कानून के प्रश्न पर गलत हो सकते हैं। यह सिद्धांत इस देश में वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले रिट क्षेत्राधिकार पर भी लागू होता है, जो कि अमलगमेटेड कोलफील्ड्स लिमिटेड और अन्य में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले से तय होता है। वि. जनपद सभा छिंदवाड़ा एवं अन्य । एआईआर 1964 एससी 1013 जहां इस न्यायालय ने कहा:

"...इसलिए, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि पुनर्न्याय का सामान्य सिद्धांत अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 226 के तहत दायर रिट याचिकाओं पर लागू होता है। इस बात पर जोर देना आवश्यक है कि सिद्धांत का अनुप्रयोग अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिकाओं पर न्यायिक निर्णय किसी भी तरह से भारत के नागरिकों को गारंटीकृत मौलिक अधिकारों की सामग्री को खराब या प्रभावित नहीं करता है। यह केवल उस तरीके को विनियमित करने का प्रयास करता है जिसमें उक्त अधिकारों को सफलतापूर्वक दावा किया जा सकता है और प्रमाणित किया जा सकता है। कानून की अदालतों में।"

19. देवीलाल मोदी बनाम एसटीओ (एआईआर 1965 एससी 1150) में इस न्यायालय की एक अन्य संविधान पीठ के फैसले द्वारा, रचनात्मक न्यायिक न्याय के सिद्धांत, जो उसी सिद्धांत का एक हिस्सा हैं, को रिट कार्यवाही पर लागू माना गया है, जहां यह न्यायालय देखा:

"श्री त्रिवेदी के पक्ष में यह स्वीकार किया जा सकता है कि वर्तमान अपील में उनके खिलाफ रचनात्मक न्यायिक निर्णय का जो नियम पेश किया गया है, वह एक तरह से सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा निर्धारित कुछ हद तक तकनीकी

या कृत्रिम नियम है। यह नियम बताता है कि यदि उसके और उसके प्रतिद्वंद्वी के बीच की कार्यवाही में एक पक्ष द्वारा याचिका दायर की जा सकती थी, उसे बाद की कार्यवाही में उसी पार्टी के खिलाफ उस याचिका को लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी जो कार्रवाई के समान कारण पर आधारित है; लेकिन मूल रूप से, यहां तक कि यह भी दृष्टिकोण सार्वजनिक नीति के समान विचारों पर आधारित है, क्योंकि यदि रचनात्मक न्यायिक न्याय का सिद्धांत रिट कार्यवाही पर लागू नहीं होता है, तो यह पार्टी के लिए एक के बाद एक कार्यवाही करने और हर बार नए आधार का आग्रह करने के लिए खुला होगा; और वह स्पष्ट रूप से है सार्वजनिक नीति के उन विचारों से असंगत है जिनका हमने अभी उल्लेख किया है।"

20. डायरेक्ट रिक्रूट क्लास-॥ इंजीनियरिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन में संविधान पीठ के फैसले का भी संदर्भ दिया जा सकता है । बनाम महाराष्ट्र राज्य (1992) 2 एससीसी 715 जहां इस न्यायालय ने एक बार फिर दोहराया कि रचनात्मक न्याय के सिद्धांत न केवल उस मामले पर लागू होते हैं जो वास्तव में किसी मामले में तय या निर्धारित होता है, बल्कि हर दूसरे मामले पर लागू होता है, जिस पर पार्टियों को मुकदमा करना चाहिए था। या जो

मुकदमेबाजी की विषय वस्तु से आकस्मिक या अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ था।

इस न्यायालय ने कहा:

".. एक निर्णय न केवल निर्धारित वास्तविक मामले के संबंध में निर्णायक और अंतिम होता है, बल्कि हर दूसरे मामले के संबंध में भी होता है, जिस पर पक्षों को मुकदमा करना चाहिए था और जिसे विषय वस्तु के साथ प्रासंगिक या अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ माना गया हो। मुकदमेबाजी और दावे और बचाव दोनों के मामलों के संबंध में मूल कार्रवाई के वैध दायरे में आने वाला हर मामला। इस प्रकार, सीपीसी की धारा 11 के स्पष्टीकरण IV में अंतर्निहित रचनात्मक न्यायिक सिद्धांत का सिद्धांत रिट मामले पर लागू किया गया था। हम, तदनुसार यह माना जाए कि रिट मामला न्यायिक आधार पर खारिज किए जाने योग्य है।"

21. यह इस न्यायालय के उपरोक्त आधिकारिक निर्णयों के प्रकाश में है कि अब अपीलकर्ताओं के लिए यह तर्क देना संभव नहीं है कि रचनात्मक न्याय के सिद्धांत उन्हें वह प्रश्न उठाने से नहीं रोकेंगे जो, जैसा कि पहले देखा गया था, उठाया जा सकता था और वास्तव में उठाया जाना चाहिए था। मुकदमेबाजी के पिछले दौर में उनके द्वारा उठाया गया था। इस मामले को

देखते हुए, उच्च न्यायालय का यह मानना पूरी तरह से न्यायसंगत था कि अपीलकर्ताओं द्वारा सिविल अपील संख्या में इस न्यायालय के 9 अप्रैल, 2008 के आदेशों द्वारा उन्हें दी गई स्वतंत्रता की कथित कवायद के तहत यह याचिका उठाई जानी थी। 2004 का.5091 कानूनी रूप से खुला नहीं था और इसे आग्रह करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

22. प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर तदनुसार दिया गया है।

पुनः प्रश्न संख्या 2

23. हालाँकि प्रश्न संख्या 1 का उत्तर अपीलकर्ताओं के विरुद्ध दिया गया है, इसलिए इस प्रश्न की जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन चूंकि मामले पर कुछ विस्तार से बहस हुई है, इसलिए हम उससे भी निपट सकते हैं।

24. अपीलकर्ताओं की ओर से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भूमि राजस्व और भूमि सुधार विनियमन, 1966 के विनियम 141 से 146 और 151 के प्रावधान पर भरोसा रखा गया था। संदर्भ की सुविधा के लिए, हम इस स्तर पर उक्त प्रावधानों को निकाल सकते हैं। "141. किरायेदारों के निम्नलिखित वर्ग होंगे, अर्थात्: -

(i) अधिभोग किरायेदार;

(ii) गैर-अधिभोग किरायेदार;

i) अनुदान प्राप्तकर्ता और; और

(iv) लाइसेंसधारी।

142. प्रत्येक व्यक्ति निम्नलिखित में से किसी एक वर्ग का होगा

अधिभोगी किरायेदार कहा जाएगा और उसके पास सभी अधिकार होंगे और वह अधीन होगा

किसी अधिभोगी किरायेदार द्वारा प्रदत्त या उस पर थोपी गई सभी देनदारियाँ

इस विनियम के अंतर्गत, अर्थात्:-

(ए) प्रत्येक व्यक्ति, जो इसके प्रारंभ होने से ठीक पहले विनियमन, ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (भूमि कार्यकाल) विनियमन, 1926 के प्रावधानों के तहत अधिभोग का अधिकार प्राप्त कर लिया था;

(बी) प्रत्येक व्यक्ति, जिसने एक गैर-अधिभोग किरायेदार के रूप में, पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल बोर्ड की स्थानीय सीमा के भीतर स्थित गैर-जोत पर खेती की है और इस विनियमन या इसके शुरू होने से दो साल की अवधि तक लगातार खेती की है। किरायेदारी, जो भी बाद में हो, इस विनियम के प्रावधानों के अनुसार है और भू-राजस्व के बकाया में नहीं है।

143. निम्नलिखित में से किसी भी वर्ग से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को गैर-अधिभोग किरायेदार कहा जाएगा और उसके पास सभी अधिकार होंगे और वह इस विनियमन के तहत या उसके तहत गैर-अधिभोग किरायेदार पर प्रदत्त या लगाए गए सभी दायित्वों के अधीन होगा, अर्थात्:-

(ए) प्रत्येक व्यक्ति, जो इस विनियमन के शुरू होने से ठीक पहले, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (भूमि कार्यकाल) विनियमन, 1926 के प्रावधानों के तहत एक गैर-अधिभोग किरायेदार था;

(बी) प्रत्येक व्यक्ति जिसे किसी कृषि भूमि के संबंध में धारा 146 के खंड (ii) के तहत लाइसेंस दिया गया है।

144 (1) निम्नलिखित में से किसी भी वर्ग से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को अनुदानग्राही कहा जाएगा और उसके पास सभी अधिकार होंगे और वह इस विनियमन के तहत या इसके तहत अनुदानग्राही पर प्रदत्त या लगाए गए सभी दायित्वों के अधीन होगा, अर्थात्: -

(ए) प्रत्येक व्यक्ति, जो इस विनियमन के शुरू होने से ठीक पहले, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (भूमि कार्यकाल) विनियमन, 1926 के तहत दिए गए अनुदान के अनुसरण में किसी भी भूमि पर कब्जा कर रहा था;

(बी) प्रत्येक व्यक्ति जिसे धारा के खंड (i) के तहत अनुदान दिया जाता है

146. (2) उप-धारा (1) में निहित किसी भी बात के बावजूद, प्रत्येक व्यक्ति, जो अधिभोगी या गैर-अधिभोग किरायेदार नहीं है, विनियम के प्रारंभ होने से ठीक पहले निकोबार में किसी भी खाते या सुपारी के बागान का कब्जा रखता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (भूमि स्वामित्व) विनियमन, 1926 के तहत दिए गए अनुदान या लाइसेंस के अनुसरण में, इस विनियमन के प्रयोजन के लिए उस अवधि के लिए अनुदान प्राप्तकर्ता माना जाएगा जैसा कि मुख्य आयुक्त अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकते हैं। समय - समय पर।

स्पष्टीकरण। - इस उपधारा में "निकोबार" का अर्थ है केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में शामिल सभी द्वीप जो 10 डिग्री चैनल के दक्षिण में स्थित हैं।

145. निम्नलिखित में से किसी भी वर्ग से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को लाइसेंसधारी में बुलाया जाएगा और उसके पास सभी अधिकार होंगे और वह इस विनियमन के तहत या उसके तहत लाइसेंसधारी पर प्रदत्त या लगाए गए सभी दायित्वों के अधीन होगा, अर्थात्: -

(ए) प्रत्येक व्यक्ति, जो इस विनियमन के शुरू होने से ठीक पहले, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (भूमि स्वामित्व) विनियमन, 1926 के

प्रावधानों के तहत दिए गए लाइसेंस के अनुसरण में किसी भी भूमि पर कब्जा कर रहा था;

(बी) प्रत्येक व्यक्ति जिसे धारा 146 के खंड (ii) के तहत किसी गैर-कृषि भूमि के संबंध में लाइसेंस दिया गया है।

146. मुख्य आयुक्त, ऐसी शर्तों पर और ऐसी शर्तों के अधीन, जिन्हें वह उचित समझे, -

(i) किसी भी व्यक्ति को नारियल, कॉफी, रबर और अन्य लंबे समय तक चलने वाली फसलों की खेती के लिए और ऐसी खेती के उद्देश्य से या उसके संबंध में उपयोग किए जाने वाले भवनों और कार्यों के निर्माण के लिए अनुदान देना। तीस वर्ष से अधिक की किसी भी अवधि के लिए भूमि, इतनी ही अवधि के लिए नवीनीकरण के विकल्प के साथ:

बशर्ते कि रबर की फसल की खेती के लिए मुख्य आयुक्त द्वारा सरकार की मंजूरी से लंबी अवधि निर्दिष्ट की जा सके

(ii) किसी भी व्यक्ति को किसी भी भूमि पर ऐसे विस्तार और ऐसे उद्देश्यों के लिए कब्जा करने के लिए लिखित रूप में लाइसेंस प्रदान करना जो निर्धारित किया जा सकता है

151. (1) एक किरायेदार निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर उप-विभागीय अधिकारी के आदेश द्वारा अपनी हिस्सेदारी से बेदखल होने के लिए उत्तरदायी होगा, अर्थात्: -

(ए) उसने कोई ऐसा कार्य किया है जो जोत वाली भूमि के लिए विनाशकारी या स्थायी रूप से हानिकारक है; या

(बी) उसने ऐसी भूमि का उपयोग उस उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया है जिसके लिए वह दी गई थी; या

(सी) उसने इस विनियमन या इसके तहत बनाए गए किसी नियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए ऐसी भूमि में अपना हित स्थानांतरित कर दिया है।

(2) उप-धारा (1) के तहत कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि उप-विभागीय अधिकारी ने नोटिस द्वारा, किरायेदार को उसकी बेदखली के खिलाफ कारण बताने के लिए नहीं बुलाया है। (3) बेदखली का कोई भी आदेश पहले दिन से पहले निष्पादित नहीं किया जाएगा। किसी भी वर्ष फरवरी या अप्रैल के 30 वें दिन के बाद।"

25. श्री कोहली द्वारा यह तर्क दिया गया कि चूंकि अपीलकर्ता अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (भूमि कार्यकाल) विनियमन, 1926 के तहत दिए

गए अनुदान के संदर्भ में विवादित भूमि पर कब्जा कर रहे थे; वे अनुदानग्राही थे और उनके पास सभी अधिकार थे और वे 1966 के विनियमों के तहत अनुदानग्राही को प्रदत्त या लगाए गए सभी दायित्वों के अधीन थे। यह तर्क दिया गया कि यद्यपि अपीलकर्ताओं के पक्ष में दिए गए अनुदान की अवधि समाप्त हो गई थी और उनके पक्ष में कोई नवीनीकरण नहीं किया गया था, ऐसे नवीनीकरण की अनुमति नहीं थी, वे विनियमन के तहत गिनाए गए एक या अधिक आधारों को छोड़कर बेदखल किए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं थे। 151 (सुप्रा)। श्री कोहली ने तर्क दिया कि उक्त विनियमों के प्रावधानों पर उनके द्वारा की गई व्याख्या के परिणामस्वरूप 1926 विनियमन के तहत दिए गए प्रत्येक अनुदान और 1966 विनियमन के तहत दिए गए अनुदान अनंत काल तक अनुदान बन सकते हैं, बशर्ते कि अनुदान प्राप्तकर्ता बेदखली के दायित्व से बच जाए। विनियमन 151 (सुप्रा) के तहत, ऐसा कोई कारण नहीं है कि उस व्याख्या से बचा जाना चाहिए, खासकर जब इसका उद्देश्य उन कब्जेदारों को लाभ पहुंचाना था जो मृतक अनुदान प्राप्तकर्ताओं के कानूनी उत्तराधिकारी हैं, जिन्हें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर अपना जीवन बिताने की निंदा की गई थी।

26. दूसरी ओर, उत्तरदाताओं की ओर से यह तर्क दिया गया कि अपीलकर्ताओं द्वारा रखी गई व्याख्या न तो विनियमों की योजना के अनुरूप

थी और न ही यह किसी ज्ञात न्यायिक सिद्धांत पर टिकाऊ थी। यह आग्रह किया गया कि विनियमन 151 (सुप्रा) एक प्रावधान था जो किरायेदारों से संबंधित है। इसका उन अनुदानों के मामलों में कोई उपयोग नहीं था जहां कब्जे में बने रहने का अधिकार समय बीतने के साथ समाप्त हो गया था जैसा कि मौजूदा मामले में है। इस संबंध में हमारा ध्यान विनियम 146 (सुप्रा) के एक प्रावधान की ओर आकर्षित किया गया था जिसके अनुसार अनुदान 30 वर्षों की अवधि के लिए दिया जा सकता है और 30 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है, इससे अधिक नहीं। यह प्रस्तुत किया गया था कि प्रावधानों को दी जाने वाली व्याख्या गलत और कानूनी रूप से अस्थिर होने के अलावा विनियमों की योजना को नकारने का प्रभाव डालेगी।

27. 1966 के विनियमों का विनियम 141 किरायेदारों के वर्गों को वर्गीकृत करता है जबकि विनियम 142 और विनियम 143 क्रमशः अधिभोग किरायेदारों और गैर-अधिभोग किरायेदारों से संबंधित हैं। यह सामान्य आधार है कि अपीलकर्ता विनियम 142 और विनियम 143 (सुप्रा) के अर्थ के भीतर अधिभोग किरायेदारों या गैर-अधिभोग किरायेदारों के विवरण का उत्तर नहीं देते हैं। उनका मामला अधिक उचित रूप से विनियमन 144 के अंतर्गत आता है जो खंड (ए) और में दो वर्गों में से किसी एक से संबंधित व्यक्तियों से संबंधित है।

(बी) उसके तहत. ऐसा इसलिए है क्योंकि अपीलकर्ताओं को 1926 विनियमों के विनियम 4(1)(ए) के तहत अनुदान प्राप्तकर्ता माना गया था, जो उक्त विनियमों के विनियम 4(1)(बी) या 1966 विनियमों के विनियम 145 के तहत आने वाले लाइसेंसधारियों से अलग है। हालाँकि, सवाल यह है कि क्या 1926 के विनियमों के तहत अनुदान प्राप्तकर्ता को 60 साल की अवधि के बाद भी कब्जे में बने रहने का कोई अधिकार है, जो कि 1966 के विनियमों के विनियम 146 के तहत अनुमेय अवधि है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि 1926 के विनियमों के तहत ऐसा कोई अधिकार नहीं पाया जा सकता है। मौजूदा मामले में अनुदान की अवधि की समाप्ति अनुदान प्राप्तकर्ताओं को प्रशासन को कब्जा सौंपने के लिए बाध्य करेगी। वर्ष 1966 के विनियमों द्वारा 1926 के विनियमों को निरस्त किए जाने के बावजूद 1926 के विनियमों के अंतर्गत वह दायित्व या देनदारी कायम रहेगी। यह 1966 के विनियमों के विनियम 211 से स्पष्ट है जो इस प्रकार है:

"211 (1) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (भूमि स्वामित्व) विनियमन, 1926 को इसके द्वारा निरस्त किया जाता है।

(2) उक्त विनियम का निरसन प्रभावी नहीं होगा, -

(ए) उक्त विनियम का पिछला संचालन या उसके तहत विधिवत किया या भुगता गया कुछ भी; या

(बी) उक्त विनियम के तहत अर्जित, उपार्जित या उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या देनदारी; या

(सी) उक्त विनियम के विरुद्ध किए गए किसी भी अपराध के संबंध में कोई जुर्माना, जब्ती या सजा; या

(डी) उपरोक्त किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, दायित्व, दंड, जब्ती या सजा के संबंध में कोई भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय, और ऐसी कोई भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय शुरू किया जा सकता है, जारी रखा जा सकता है या लागू किया जा सकता है, और कोई भी ऐसा जुर्माना, जब्ती या सजा दी जा सकती है जैसे कि उक्त विनियमन निरस्त नहीं किया गया हो।

(3) उप-धारा (2) में निहित प्रावधानों के अधीन, उक्त विनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किया गया कोई भी कार्य या कोई कार्रवाई, जहां तक यह इस विनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं है, मानी जाएगी। इस विनियम के तहत किया गया है या लिया गया है और यह

तब तक लागू रहेगा जब तक कि इस विनियम के तहत की गई किसी भी कार्रवाई से इसका स्थान न ले लिया जाए।"

(जोर दिया गया)

28. यदि समाप्त हो चुके अनुदान के अनुदानग्राही ने दी गई संपत्ति का कब्जा सौंपने का दायित्व वहन किया है, तो ऐसा दायित्व उन विनियमों के निरस्त होने के बावजूद भी लागू रहेगा, जिनके तहत ऐसी देनदारी उत्पन्न हुई थी। यह तर्क कि 1966 के विनियमों के विनियम 144(1)(ए) के कारण दायित्व समाप्त हो जाता है, हमारी राय में, कानूनी रूप से अनुचित है। हम ऐसा दो कारणों से कहते हैं। सबसे पहले, क्योंकि विवाद विनियम 211 के सामने खड़ा है जो 1926 के विनियमों के तहत किए गए दायित्व को जारी रखता है। जब तक निरसन विनियमन द्वारा देय दायित्व को मान्यता दी जाती है और जारी रखा जाता है, तब तक उसे कानून में लागू किया जा सकता है। दूसरे, क्योंकि विनियम 144(1)(ए) की व्याख्या स्वयं ऐसी स्थिति को स्वीकार नहीं करती है जहां कब्जा छोड़ने का दायित्व न केवल विलुप्त हो जाता है, बल्कि अनंत काल तक कब्जे में रहने के अधिकार में विस्तारित हो जाता है। हमारी राय में, विनियम 144 में जो कुछ भी निर्धारित है, वह यह है कि पुराने विनियमों के तहत अनुदान प्राप्तकर्ता उसी दायित्व/दायित्व के अधीन रहेगा या 1966 विनियमों के तहत अनुमत समान अधिकारों का आनंद

उठाएगा। हालाँकि, जारी रखने का अधिकार इस बात पर निर्भर करेगा कि कब्जे वाले व्यक्ति के पास उसके पक्ष में वैध अनुदान है, यहाँ तक कि 1966 के विनियम लागू होने की तारीख पर भी। यदि उत्तर सकारात्मक है, तो ऐसे अनुदान को 1966 के विनियमों के तहत अनुदान माना जा सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यह वास्तव में 1926 के विनियमों के तहत एक अनुदान था।

29. अनुदान की शेष अवधि की सीमा तक, 1966 के विनियमों के लागू होने की तारीख तक, अनुदान प्राप्तकर्ता अपने अधिकार का आनंद लेता रहेगा और 1966 के विनियमों के तहत दायित्व के अधीन रहेगा। हालाँकि, अनुदान की अवधि समाप्त होने पर, अनुदान प्राप्तकर्ता कब्जा छोड़ने के लिए उत्तरदायी होगा, जैसे अनुदान प्राप्तकर्ता 1966 विनियमों के तहत दिए गए अनुदान के संबंध में विनियम 146 के तहत करने के लिए उत्तरदायी है। जहां तक अनुदान प्राप्तकर्ता के कब्जे को जारी रखने के अधिकार का सवाल है, विनियम का सार 1926 के विनियमों और वर्ष 1966 के बाद के विनियमों के तहत समान है।

30. किसी भी मामले में, अनुदान प्राप्तकर्ता 60 वर्ष से अधिक समय तक कब्जे में नहीं रह सकता है। इसलिए, इस तर्क पर ध्यान देने की जरूरत है कि एक पुराना अनुदान प्राप्तकर्ता तब तक कब्जे में रह सकता है जब तक

कि विनियमन 151 का कोई उल्लंघन न हो। वर्तमान मामले में, अपीलकर्ताओं को इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्हें 1966 के विनियमों के तहत सुरक्षा मिल सकती है क्योंकि उनके पक्ष में अनुदान को 1994 तक नवीनीकृत माना जाता था, जो 1966 में अस्तित्व में था, लेकिन ऐसी सुरक्षा 60 साल की अवधि की समाप्ति के साथ समाप्त हो जाएगी। 1994.

31. इस मामले में हमें प्रश्न संख्या 2 का नकारात्मक उत्तर देने में कोई झिझक नहीं है।

32. परिणामस्वरूप यह अपील विफल हो जाती है और इसे खारिज कर दिया जाता है, लेकिन लागत के बारे में कोई आदेश दिए बिना।

.....जे.

(टीएस ठाकुर).....जे।

(सी. नागप्पन) नई दिल्ली 7 मार्च 2014

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी पुरुषोत्तम मिश्रा (आर.जे.एस.) (UID:RJ1270) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।